Conference on Children by Indian Law Institute

1864. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAM BHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the deliberations made on March, 21, 1994 at the inauguration of a conference on Children, evironment and Human Health, organised by the Indian Law Institute, calling for a holistic approach for children environment and health and for enactment of laws for protection and promotion of the Rights of the child, especially the girl child, who is discriminated against in most of the society; and

(b) if so, whether during the current decade for the girl child, any specific laws have been or are proposed to be enacted and other steps taken to abolish child labour especially the bonded girl child labour and if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LBOUUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वेतन और भत्ते

1865. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों के संबंध में वर्ष 1983 को आधारभूत वर्ष मान कर वर्ष 1993 में उनके वेतन तथा भत्तों का निर्धारण किया है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान मूल्यों के आधार पर वेतन तथा भत्ते देने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ग) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कर्मकारों के वेतन और भत्तों को भिन्न-भिन्न तंत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में, केन्द्रीय सरकार ने 12-7-94 को खनन, निर्माण और रेलवे क्षेत्रों से संबंधित 39 अनुसूचित नियोजनों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरो मे संशोधन कर दिया है। मजदूरी को 31-12-93 को समाप्त होने वाली पूर्ववर्ती छमाही के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अर्थात् 1281 (आधार 1960=100) के संदर्भ मे संशोधित किया गया था। केन्द्रीय क्षेत्र में कृषि कर्मकारों के लिए मजदूरी को 31-12-1990 को समाप्त होने वाली छमाही के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात् 917 (आधार 1960-61=100) के संदर्भ में 12-8-92 को संशोधित किया गया था। मूल्य सूचकांक में हुई बढ़ोत्तरी की क्षतिपूर्ति करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध परिवर्त्ती महंगाई भत्ते के घटक की भी व्यवस्था की गयी है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर पिछली बार 1-1-86 से उस समय विद्यमान मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए संशोधित किए गए थे। तत्पश्चात्, मूल्य सूचकांक में हुई बढ़ोत्तरी की क्षतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर महंगाई भत्ता प्रदान करके की जाती है।

Centrally Sponsored Projects going Cost/ Time Overruns

1866. SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether almost all Centrally run/ sponsored projects are going through cost as well as time overrun; and

(b) if so, what steps have been taken to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) No, Sir. As on June 1994, out of 369 projects costing Rs. 20 crores and above on the monitor of the Department of Programme Implementation, 109 projects had both time and cost overruns with respect to their latest approved schedule and cost.

(b) The steps taken to improve the situation are:

(i) Intensive monitoring of project by the project authorities and the Department of Programme Implementation through Monthly/Quarterly Monitoring System.

(ii) Indepth periodical review of progress by Administrative Ministries and constant pressure on the project authorities for expeditious completion.

(iii) Setting up of Task Force/Empowered Committees for speedy finalisation of contract packages, solving land acquisition and other problems.

(iv) Close follow up by concerned Ministries and projects authorities with the State Governments, Equipment suppliers, contractors, consultants and other concerned agencies to minimise delays.